यूएस में रहने के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहा ईबी-5 वीजा

नई दिल्ली, 7 मई (ए)। एच-1बी वीजा के लगातार सख्त होते नियमों के बीच एक नया वीजा प्रोग्राम तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस वीजा प्रोग्राम का नाम ईबी-5 है। अक्तूबर, 2016 से 2017 तक 174 भारतीयों को यह वीजा जारी किया गया है। इस साल भी 149 वीजा जारी किए जा चुके हैं। ईबी-5 वीजा प्रोग्राम से यू.एस. में कानूनी रूप से स्थायी निवास पाया जा सकता है। हालांकि इसमें नागरिकता नहीं मिलेगी। अमरीका के ईबी-5 वीजा के लिए 5 लाख डॉलर का निवेश करना होता है। इसके बाद पूरे परिवार को ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ईबी-5 ब्रिक्स के सी.ई.ओ. विवेक टंडन ने कहा कि ईबी-5 वीजा प्रोग्राम पिछले 30 वर्षों से चलन में है। 2015 से इसकी निवेश राशि को बढ़ाने के कई प्रस्ताव आए हैं लेकिन इसका प्रभाव वीजा का आवेदन करने वाले लोगों की संख्या पर पड़ सकता था। गौरतलब है कि एच-1 वीजा धारकों के जीवन साथी को एच-4 वीजा जारी किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में उच्च कौशल वाले भारतीय पेशेवर शामिल हैं। ओबामा प्रशासन के फैसले से भारतीय अमरीकियों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा था। एच-4 वीजा धारकों में 90 प्रतिशत भारतीय हैं।

शेयर बाजार में नहीं गल रही बेईमान कंपनियों की दाल

नई दिल्ली, 7 मई (ए)। कंपनियों की बेईमानी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उनकी चूक को जरा-सी भी छूट नहीं देते हुए घरेलू शेयर बाजार के सतर्क निवेशक पूर्ण पारदर्शिता और नियमों की पूरी अनुपालना की उम्मीद करने लगे हैं। उद्योग संगठन एसोचैम ने रविवार को कहा कि घरेलू शेयर बाजार में अब कंपनियों की कोई भी बेईमानी नजरअंदाज नहीं की जाती। निवेशक में ऐसी कंपनियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। निवेशक अब उम्मीद करने लगे हैं कि कंपनियां कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अनुपालना करें और पारदर्शिता का रवैया न अपनाने पर उन्हें सजा भी दे रहे हैं। संगठन ने निवेशकों की जागरूकता को देखते हुए कंपनियों के प्रवर्तकों को सलाह दी है कि वे शेयरधारकों के मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। संगठन का कहना है कि अब वे दिन गए जब कोई कंपनी या उसके प्रवर्तक नियम-कायदे का उल्लंघन करने पर भी बच जाते थे। निवेशकों के जागरूक होने और सख्त नियमों के कारण अब कोई भी कंपनी जाने या अनजाने कुछ भी गलत करने का जोखिम नहीं उठा सकती है। इसका उदाहरण पिछले दिनों कई बार सामने आया है जबकि संदेहों में घिरी कंपनियों के शेयरों की कीमत में तेज गिरावट आई और उनका बाजार पूंजीकरण काफी घट गया।

सेंसेक्स में 293 अंकों की तेजी

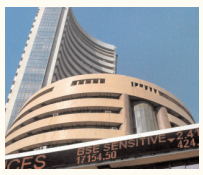

मुंबई ,07 मई (ए)। देश के शेयर बाजारों में सोमवार को तेजी दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 292.76 अंकों की तेजी के साथ 35,208.14 पर और निफ्टी 97.25 अंकों की गिरावट के साथ 10,715.50 पर बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 68.21 अंकों की तेजी के साथ 34,983.59 पर खुला और 292.76 अंकों या 0.84 फीसदी की तेजी के साथ 35,208.14 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स ने 35,259.81 के ऊपरी और 34,977.74 के निचले स्तर को छुआ।

बीएसई के मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में भी तेजी रही। मिडकैप सूचकांक 91.37 अंकों की तेजी के साथ 16,652.38 पर और स्मॉलकैप सूचकांक 100.28 अंकों की तेजी के साथ 18,091.73 पर बंद हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी सुबह 34.9 अंकों की तेजी के साथ 10,653.15 पर खुला और 97.25 अंकों या 0.92 फीसदी की तेजी के साथ 10,715.50 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में निफ्टी ने 10,725.65 के ऊपरी और 10,635.65 के निचले स्तर को छुआ।

बीएसई के 19 में से 17 सेक्टरों -धातु (1.68 फीसदी), तेल और गैस (1.64 फीसदी), रियल्टी (1.51 फीसदी), ऊर्जा (1.47 फीसदी) और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं (1.45 फीसदी)- में सर्वाधित तेजी रही।

एयरलाइन स्टॉक्स ने दिया झटका

3 दिन में निवेशकों के डूब गए 10,050 करोड़ रुपए

नई दिल्ली, 7 मई (ए)। एयरलाइन कंपनियों के स्टॉक्स ने इस महीने निवेशकों को तगड़ा झटका दिया है। इस महीने सिर्फ 3 दिन के कारोबार में एयरलाइन स्टॉक्स 20 फीसदी तक टूटे हैं। फ्यूल कॉस्ट में बढ़ोतरी और इंटरग्लोबल एविएशन के कमजोर तिमाही नतीजे ने निवेशकों के सैंटीमैंट्स पर असर डाला है। तीन लिस्टेड एयरलाइनों में से जैट एयरवेज और स्पाइसजेट ने अभी तक अभी तक 2017-18 के लिए अपनी चौथी तिमाही के नतीजे घोषित नहीं किए हैं।

बजट कैरियर इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने 2 मई को चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 73 फीसदी घटकर 117.64 करोड़ रुपए रह गया। फ्यूल कॉस्ट में बढ़ोतरी और फॉरेन एक्सचेंज लॉस की वजह से मार्च क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा घटा है।

क्रूड प्राइस में तेजी का प्रेशर: विशेषज्ञों के मुताबिक ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस में तेजी की इक्षचता से एयरलाइन कंपनियों के प्रॉफिट पर दबाव बन सकता है। मई महीने के तीन ट्रेड्इडग सैशन में बी.एस.ई. पर इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक 15.57 फीसदी टूटा है। जैट एयरवेज का स्टॉक 20 फीसदी गिरा है जबकि स्पाइसजेट में उतार-चढ़ाव का ट्रैंड है। इंटरग्लोब एविएशन के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद स्पाइसजेट के शेयरों में 6 फीसदी की गिरावट आई लेकिन कारोबार के अंत में स्टॉक हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। इंटरग्लोबल एविएशन, जेट एयरवेज और स्पाइसजेट के शेयरों में गिरावट से इस महीने में अभी तक निवेशकों के 10,050 करोड़ रुपए डूब गए हैं। सैमको सिक्युरिटीज के फाउंडर एंड सी.ई.ओ. जिमीत मोदी का कहना है कि इस हफ्ते एयरलाइन स्टॉक में कमोजरी देखी गई है, जो हाल के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट है।

10 साल में दोगुनी हो सकती है भारत की अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली, 7 मई (ए)। एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) के मुख्य अर्थशास्त्री यासुयूकी सवादा ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की 7 प्रतिशत से अधिक अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर आश्चर्यजनक रूप से काफी तेज है और अगर यह गति बनी रहती है तो अर्थव्यवस्था का आकार एक दशक के भीतर ही दोगुना हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश को 8 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल नहीं करने को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए लेकिन आय विषमता दूर कर घरेलू मांग बढ़ाने पर गौर करना चाहिए। सवादा ने कहा कि वृद्धि को निर्यात की तुलना में घरेलू खपत से अधिक गति मिल रही है।

10 साल दोगुनी होगी अर्थव्यवस्था : ए.डी.बी. ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2018-19 में 7.3 प्रतिशत तथा 2019-20 में 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2017-18 में 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो कि इससे पिछले वर्ष 2016-17 के 7.1 प्रतिशत से कम है। एडीबी के मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा, ''7प्रतिशत वृद्धि आश्चर्यजनक रूप से काफी तेज है। अगर 7 प्रतिशत वृद्धि 10 साल तक बनी रहती है तो अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना हो जाएगा।''

2025 तक 5,000 अरब डॉलर : उन्होंने कहा, ''यह वृद्धि दर काफी तेज है और क्षेत्र की सबसे बड़े आकार वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के चलते चालू वित्त वर्ष में 7.3 प्रतिशत तथा अगले वित्त वर्ष में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि वास्तव में आश्चर्य जनक है।'' भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2500 अरब डॉलर है और इस लिहाज से यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने हाल में कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था दोगुनी होने के रास्ते पर है और 2025 तक 5,000 अरब डॉलर की हो जाएगी। सवादा ने कहा कि हालांकि 8 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करना फिलहाल भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। 7 प्रतिशत वृद्धि भी अच्छा आंकड़ा है और भारत को 8 प्रतिशत वृद्धि हासिल नहीं करने को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए।

क्षतिग्रस्त फसल का बैंक ने मुआवजा दिया कम, करेगा ब्याज सहित भुगतान

रतलाम, 7 मई (ए)। एक किसान की फसल ओलावृष्टि दौरान क्षतिग्रस्त हो गई जिसका मुआवजा बैंक ने बहुत कम दिया, जिसे फोरम ने गलत बताते हुए बैंक को सही मुआवजा ब्याज सहित देने का आदेश दिया।

बड़गांव जिला उज्जैन निवासी भगवान सिंह पुत्र मान सिंह की रतलाम के ग्राम सिनोद में 1.770 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जिस पर वर्ष 2015-16 में उसने सोयाबीन बोई थी। बैंक ऑफ इंडिया की भाटपचलाना शाखा से किसान क्रैडिट कार्ड जारी होने पर बैंक ने फसल बीमा की प्रीमियम राशि 984.56 रुपए खाते से काटी थी। ओलावृष्टि से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। सिनोद के मौजा पटवारी ने इसका आकलन किया। बैंक ने मुआवजे के 1831 रुपए भुगतान किए, जबकि गांव के अन्य कृषकों को 1200 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से भुगतान हुआ। भगवान सिंह ने परेशान होकर उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। जिला उपभोक्ता फोरम ने बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को 30 दिन में 1200 रुपए बीघा के हिसाब से किसान को मुआवजा राशि 6 प्रतिशत वार्षिक दर से भुगतान करने का आदेश दिया।

PF पर मिल सकता है 8.55% ब्याज

नई दिल्ली, 7 मई (ए)। श्रम मंत्रालय वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भविष्य निधि (पीएफ) पर देय ब्याज की दर 8.55 फीसदी इसी सप्ताह नोटिफाई कर सकता है। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) द्वारा अपने लगभग 5 करोड़ अंशधारकों के खातों में रिटर्न डालने का मार्ग प्रशस्त होगा।

वित्त मंत्रालय बीते वित्त वर्ष के लिए ई.पी.एफ. पर 8.55 फीसदी की ब्याज दर की पुष्टि कर चुका है। यह बीते 5 साल में पीएफ पर सबसे कम दर होगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'कर्नाटक में चुनावों के कारण आचार संहिता को देखते हुए श्रम मंत्रालय ने ब्याज दर अधिसूचित करने के लिए निर्वाचन आयोग से मंजूरी मांगी है ताकि ब्याज राशि अंशधारकों के खातों में डाली जा सके।' सूत्र ने कहा, 'ई.पी.एफ.ओ. के अंशधारकों को 8.55 फीसदी ब्याज दर उपलब्ध कराने की मंजूरी इस सप्ताह कभी भी मिल सकती है।' उल्लेखनीय है कि ई.पी.एफ.ओ. का केंद्रीय न्यासी बोर्ड ब्याज दर के बारे में अपनी सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेजता है।

जीएसटी रिटर्न का मिलान नहीं होने पर कंपनियों को नोटिस

नई दिल्ली, 7 मई (ए)। माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अधिकारियों ने उन कंपनियों को जांच के नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जिनका कर भुगतान उनके अंतिम बिक्री रिटर्न से मेल नहीं खाता है। राजस्व विभाग ने पाया कि 34 प्रतिशत कंपनियों ने कम जी.एस.टी. का भुगतान किया है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी है। इनके अलावा उन कंपनियों को भी नोटिस मिला है जिनका अंतिम बिक्री रिटर्न 'जी.एस.टी.आर-1' और खरीद रिटर्न 'जी.एस.टी.आर-2 ए' आपस में मेल नहीं खाते हैं।

राजस्व विभाग द्वारा मार्च में किए गए आकलन के अनुसार 34 प्रतिशत कंपनियों ने जुलाई-दिसम्बर के दौरान प्रारंभिक सारांश रिटर्न 'जी.एस.टी.आर-3 बी' दायर करने में 34,400 करोड़ रुपए कम कर का भुगतान किया है। इन कंपनियों ने जी.एस.टी.आर.-3 बी के तहत 8.16 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जबकि जी.एस.टी.आर.-1 के अनुसार इन्हें 8.50 लाख करोड़ रुपए कर का भुगतान करना था। गुजरात जी.एस.टी. आयुक्त कार्यालय द्वारा 4 मई को जारी एक नोटिस में करदाताओं से 14 मई तक अक्तूबर-दिसम्बर अवधि के लिए दायर जी.एस.टी.आर.-3 बी और जी.एस.टी.आर.-1 में असमानता का कारण बताने को कहा गया है।

एक मासिक रिटर्न से जी.एस.टी. अनुपालन होगा सरलः वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) के अनुपालन विशेषकर रिटर्न भरने को लेकर करदाताओं की इक्षचताओं को दूर किए जाने और अब सिर्फ एक ही मासिक रिटर्न भरने की व्यवस्था से इसका अनुपालन सरल हो गया है। विश्लेषकों का कहना है कि अब तक जी.एस.टी. के लिए पूरे एक साल में 36 रिटर्न भरने की व्यवस्था थी।

हालांकि अभी सिर्फ एक ही रिटर्न जी.एस.टी.आर. श्री बी भरा जा रहा था लेकिन करदाता इसको लेकर इक्षचतित थे कि आगे चलकर उसे हर महीने 3 रिटर्न भरने पड़ेंगे लेकिन जी.एस.टी. परिषद की 27वीं बैठक में इसका समाधान कर दिया गया है। अब कंपोजिशन स्कीम के डीलरों और शून्य लेनदेन वाले डीलरों को छोड़कर सभी करदाता एक ही मासिक जी.एस.टी. रिटर्न भरेंगे।

बैंक कर्मचारी करेंगे 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल

नई दिल्ली, 7 मई (ए)। बैंक कर्मचारी यूनियनों ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के सैलरी में 2 फीसदी की बढ़ोत्तरी के ऑफर को खारिज कर दिया और संगठन ने अपनी मांगों को लेकर मई महीने में हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।

9 मई को करेंगे हड़ताल: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के संगठन एआईबीओसी के जनरल सेक्रेटरी डीटी फ्रांको ने एक बयान में कहा कि आईबीए का शुरुआती ऑफर महज 2 फीसदी बढ़ोत्तरी का था, जिसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया। यूएफबीयू को 9 इम्प्लॉइज और ऑफिसर्स यूनियंस को मिलाकर बनाया गया है। फोरम ने निर्णय लिया कि 9 मई को देश के लगभग 10 लाख बैंक कर्मी 2 दिन हड़ताल करेंगे।

खारिज किया 2 फीसदी वेतन वृद्धि का ऑफरः शनिवार को हुई मीटिंग में आईबीए द्वारा रखे गए 2 फीसदी के ऑफर को खारिज कर दिया गया। पिछली वेतन वृद्धि में आईबीए ने 15 फीसदी बढ़ोतरी की थी। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (ए.आई.बी.ई.ए.) के महासचिव सी. वेंकटचलम ने बताया कि बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन संशोधन एक नवम्बर, 2017 से बकाया है। वित्त मंत्रालय ने बैंक प्रबंधनों और आई.बी.ए. को इस विषय पर चर्चा पूरी करके एक नवम्बर 2017 से संशोधित वेतन जारी की सलाह दी थी। इस पर आई.बी.ए. और बैंक यूनियनों की मई 2017 में शुरू हुई चर्चा कई दौर तक चली लेकिन आई.बी.ए. वेतन संशोधन के किसी प्रस्ताव लिए आगे नहीं बढ़ी।

महीने भर में बाकी राज्यों में भी लागू होगा इंट्रा-स्टेट E-way bill

नई दिल्ली 7 मई (ए)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत माल परिवहन के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। देशभर में अंतर-राज्यीय (इंटर-स्टेट) कारोबार के लिए ई-वे बिल लागू होने के महज एक महीने के भीतर 18 राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों में इंट्रा-स्टेट (राज्य के भीतर) ई-वे बिल की व्यवस्था को लागू किया जा चुका है।

अगले एक महीने के भीतर बाकी राज्यों में भी इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल की व्यवस्था लागू हो जाएगी। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि हर दिन 12 लाख से अधिक ई-वे बिल जारी हो रहे हैं। टैक्स अधिकारियों ने प्रभावी ढंग से ई-वे बिल की व्यवस्था का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है।

जिन राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में अब तक इंट्रा स्टेट ई-वे बिल सिस्टम लागू नहीं किया गया है, वहां एक महीने के भीतर यह काम कर लिया जाएगा। इसके लिए केंद्र ने अपने टैक्स अधिकारियों को राज्यों के टैक्स अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि जीएसटी कानून के तहत 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के माल की ढुलाई के लिए ई-वे बिल अनिवार्य किया गया है। जीएसटी काउंसिल ने 10 मार्च को हुई बैठक में एक अप्रैल से देशभर में इंटर-स्टेट कारोबार के लिए ई-वे बिल लागू करने का फैसला किया था।

इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल का क्रियान्वयन विभिन्न राज्यों में चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड समेत अब तक 18 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों ने इंट्रा-स्टेट कारोबार के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था लागू कर दी है। ई-वे बिल की व्यवस्था से कर चोरी रुकने की उम्मीद जताई जा रही है। इसे कारोबारियों के लिए भी मुफीद साबित हो रहा है। जीएसटी रिटर्न मिसमैच पर नोटिस भेजना शुरू नई दिल्ली, प्रेट्र = जीएसटी रिटर्न में अंतर को लेकर अधिकारियों ने संबंधित कंपनियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। नोटिस उन कंपनियों को भेजे जा रहे हैं जिनके भुगतान किए गए टैक्स और अंतिम बिक्री रिटर्न में अंतर मिला है।

Jaypee इंफ्राटेक के ग्राहकों से कहा- घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो

नई दिल्ली, 7 मई (ए)। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही जेपी इंफ्राटेक के घर खरीदारों के एक समूह ने अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) अनुज जैन को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी समाधान योजना को अंतिम रूप देते समय नोएडा स्थित जेपी विशटाउन परियोजना में फ्लैट बुक करने वाले हजारों खरीदारों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

खरीदारों ने जेपी इंफ्राटेक के लिए बोलीदाताओं द्वारा पेश किए गए ऋण-समाधान के मूल्यांकन के लिए अपनाए गए मानदंडों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे मनमाना और वित्तीय कर्जदाताओं के पक्ष में बताया। कर्ज चुकाने में नाकाम रहने के बाद जेपी समूह की कंपनी जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिए लक्षद्वीप बोलीदाता की दौड़ में सबसे आगे है, इस पर कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) सात मई को आयोजित बैठक में विचार करेगी। खरीदारों ने चिट्ठी में

कहा कि घर खरीदारों ने कंपनी को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है जबकि इसके मुकाबले वित्तीय कर्जदाताओं ने करीब 9,800 करोड़ रुपए दिए हैं। इस लिहाज से घर खरीदारों की हिस्सेदारी वित्तीय कर्जदाताओं की हिस्सेदारी से 1.4 गुना अधिक है। हालांकि, कर्जदाताओं को ग्राहकों से 1.6 गुना ज्यादा महत्व दिया गया है।

घर खरीदारों के समूह ने कहा है, ''हमारा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के आपत्तिजनक मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर किसी भी बोली को अंतिम रूप देना न तो सही है और न ही इसकी अनुमति दी जा सकती है।'' समूह ने कहा कि कोर्ट चाहता है कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। जेपी इंफ्राटेक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 32,000 फ्लैट तैयार कर रहा है। इसमें से अब तक वह 9,500 फ्लैट का ही कब्जा दे पाया है। इसके अलावा 4,500 अन्य फ्लैट के लिए उसने सुपुर्दगी प्रमाणपत्र के लिये आवेदन किया है।